समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

ट्रंप नरम हुए ? US से बनने वाली है बात — भारत पर लगे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने की तैयारी

Publisher

Published on 18 Sep 2025

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ था। अमेरिका ने भारत से आयातित कई उत्पादों पर 25% का **अतिरिक्त टैरिफ** लगाया था, जिसे भारत ने "दंडात्मक शुल्क" करार दिया था। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इस अतिरिक्त टैरिफ को हटाने की तैयारी में है।

यह फैसला न सिर्फ भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नया मोड़ ला सकता है बल्कि भारतीय उद्योगों और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि

अमेरिका ने यह 25% अतिरिक्त टैरिफ मुख्य रूप से रूस से भारत के कच्चे तेल आयात और कुछ अन्य नीतिगत असहमति के कारण लगाया था। इसके अलावा, पहले से ही 25% का **reciprocal tariff** दोनों देशों के बीच लागू था। यानी भारतीय उत्पादों पर कुल 50% तक का शुल्क लग रहा था।

इससे अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता घट गई और निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ा। खासकर **टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी** जैसे सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा।

नवीनतम घटनाक्रम

भारत के **मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. आनंदा नागेश्वरन** ने हाल ही में कहा कि अमेरिका जल्द ही इन अतिरिक्त टैरिफ को हटाने की दिशा में कदम उठा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में **penal tariff हट सकता है** और मौजूदा reciprocal tariff को भी 10–15% के स्तर तक घटाने पर बातचीत हो रही है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय व्यापार वार्ताएँ लगातार जारी हैं। दोनों पक्षों की कोशिश

है कि एक संतुलित व्यापार समझौता हो सके जिससे दोनों देशों को दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

भारत की प्रमुख दलीले

भारत ने अमेरिका के सामने कई अहम बिंदु रखे हैं:

1. **निर्यातकों को नुकसान** – अतिरिक्त शुल्क से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो रहे हैं और यह छोटे व मध्यम उद्योगों (SMEs) के लिए भारी झटका है।
2. **द्विपक्षीय व्यापार संतुलन** – भारत चाहता है कि व्यापारिक रिश्ते आपसी लाभकारी हों, न कि किसी एकतरफा दबाव पर आधारित।
3. **रूस से तेल आयात पर स्पष्टता** – भारत ने साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है।

अमेरिका की शर्तें

अमेरिका इस टैरिफ में नरमी दिखाने को तैयार तो है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं:

- भारत **रूस से कच्चे तेल की खरीद पर संतुलन बनाए**।
- कृषि और डेयरी सेक्टर में **अमेरिकी कंपनियों को बाजार पहुँच (Market Access)** दी जाए।
- ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड जैसे नए क्षेत्रों में अमेरिका को अवसर मिलें।

भारत फिलहाल कृषि और डेयरी सेक्टर में किसी बड़े समझौते को लेकर सतर्क है क्योंकि यह उसके घरेलू किसानों और उद्योगों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है।

निर्यातकों और भारतीय उद्योगों पर असर

यदि अमेरिका अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा देता है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलेगा।

- **लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री** – लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धा बेहतर होगी।
- **टेक्सटाइल और गारमेटं सेक्टर** – अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिलेंगे, खासकर छोटे और मंझोले उद्यमों के लिए।
- **जेम्स एंड ज्वेलरी** – उच्च टैक्स से प्रभावित यह सेक्टर फिर से अमेरिकी ग्राहकों तक पहुँच बना सकेगा।
- **IT और इंजीनियरिंग गुड्स** – शुल्क घटने से ऑर्डर्स और निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है।

साथ ही, निवेशकों और विदेशी कंपनियों का भरोसा भी बढ़ेगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते स्थिर और दीर्घकालीन हैं।

चुनौतियाँ अभी भी बरकरार

भले ही संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन अभी कई चुनौतियाँ बाकी हैं:

- **वार्ताओं मे संमय** – व्यापार समझौते रातों-रात नहीं होते। शर्तों पर सहमति बनाने में महीनों लग सकते हैं।
- **अमेरिका की आंतरिक राजनीति** – ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताएँ बदल भी सकती हैं, जिससे नीति पर असर पड़ेगा।
- **भारत की सीमाएँ** – कृषि, डेयरी और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में भारत आसानी से समझौता नहीं कर सकता।
- **अन्य वैश्विक दबाव** – चीन और यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते भी इन वार्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर के पार जाए। इसके लिए जरूरी है कि टैरिफ जैसी

अड़चनों को हटाया जाए। अगर अमेरिका 25% अतिरिक्त शुल्क हटा देता है, तो यह दोनों देशों के लिए "**विन-विन स्थिति**" होगी।

भारत को चाहिए कि वह इस मौके का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों में भी अपने निर्यात को विविध बनाए।

अमेरिका का भारत पर लगाए गए **25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने का संकेत** आने वाले समय में बड़ी आर्थिक राहत ला सकता है। यह कदम भारतीय निर्यातकों और उद्योगों को नई ऊर्जा देगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को नई दिशा प्रदान करेगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.